प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एंव निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 20 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 16 – 23 मई 2016 मूल्य पांच रूपए

मुख्य सचिव की नियुक्ति

पूर्व कर्मचारी नेता गोयल ने फारखा पर लगाये गंभीर आरोप

राष्ट्रपति,प्रधान मन्त्री से लेकर मुख्यमन्त्री तक को भेजी शिकायत

शिमला/शैल। प्रदेश के पर्यटन विकास निगम में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलन्द करने वाले निगम के पूर्व कर्मचारी नेता ओम प्रकाश गोयल ने एक बार फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यन्त्री और शान्ता कुमार आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह तथा प्रदेश संयोजक राजन सुशांत के नाम भेजे पत्र के माध्यम से नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। इस बार गोयल ने मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव एंवम अतिरिक्त मुख्य सचिव वी सी फारखा को फिर से निशाने पर लिया है। गोयल ने फारखा की ईमानदारी और निष्ठा पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह से आग्रह किया है कि यदि फारखा का मुख्य सचिव पदोन्नत किया जाता है तो वह इस मामले को प्रदेश उच्च न्यायालय में ले जायेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। गोयल ने इसी संद्धर्भ मे भेजी अपनी पुरानी शिकायतों का भी मुख्यमन्त्री को स्मरण दिलाया है जिन पर अभी तक वांच्छित कारवाई नही हुई है। गोयल की इस शिकायत के तथ्यों से जहां फारखा के विरोधीयों को उनके खिलाफ एक कारगर हथियार मिल जायेगा वहीं पर वीरभद्र सिंह की भ्रष्टाचार के खिलाफ सारी प्रतिबद्धता भी कसौटी पर लग जायेगी। क्योंकि फारखा वीरभद्र सिंह के विश्वस्त है और इसी नाते वरियता क्रम को नजर अंदाज करके उन्हें मुख्य सचिव बनाने की मंशा रखे हुए है। जबकि वरियता में उपमा चौधरी जैसे अधिकारी भी है जिनके खिलाफ कुछ भी नही है और Outstanding ACR's लिये हुए है।

इस परिदृश्य में गोयल के पत्र को नजर अन्दाज कर पाना आसान नही होगा क्योंकि हर आरोप की पुष्टि में प्रमाणिक दस्तावेज साथ लगाये हुए हैं। गोयल का आरोप है कि वर्ष 2001 से 2002 में जब फारखा पर्यटन निगम प्रबन्धन के प्रबन्ध निदेशक थे तब उन्होने होटल पीटर हॉफ में अपने मेहमानों को मुफ्त में ठहरा कर निगम को वित्तिय नुकसान पंहुचाया है। यह मेहमान जून 2002 में ठहरे थे और गोयल ने होटल पीटर हॉफ के इस संबध में बिल साथ लगाये हैं। जिन पर एम डी के गेस्ट' स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। गोयल ने जब इस आश्य की शिकायत निदेशक मण्डल से की थी तब फारखा ने अपने मेहमानों को मुफ्त में ठहराने से सिरे से ही नकार दिया था। लेकिन गोयल ने 12 मार्च 2015 को लिखे पत्र मे इस आरोप को दस्तावेज लगाकर प्रमाणित कर दिया पर इस पर कारवाई कोई नही हुई।

गोयल का आरोप है कि फारखा के गल्त फैसले के कारण पर्यटन निगम को 72 लाख का जुर्माना भरना पड़ा है। फारखा ने मार्च 2002 में निगम के वित्त प्रबन्धक को निर्देश दिये की कर्मचारियों का सी पी एफ प्रोविडैन्ट फण्ड कमीशनर के यहां जमा न करवाया जाये। दो वर्ष तक सी पी एफ जमा न करवाने के मामले में गोयल ने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका CWP 108/2002 दायर की थी जिसके परिणाम स्वरूप प्रोविडैन्ट फण्ड कमीशनर ने निगम को 72 लाख का दण्ड लगाया।

फारखा पर भारत सरकार में भी झूठे दस्तावेज फाईल करने का भी आरोप है। यह आरोप निगम के खड़ा पत्थर प्रौजैक्ट को लेकर है। इस प्रौजैक्ट को लेकर 2002 में भारत सरकार के पर्यटन मन्त्रालय में यह दस्तावेज फाईल किये गये यह प्रौजैक्ट पूरी तरह तैयार करके 31-12-2001 को चालू भी कर दिया गया है इन दस्तावेजों में बाकायदा उपयोगिता प्रमाण पत्र तक फाईल किया गया है। प्रमाण पत्र और इसके चालू भी कर दिये जाने पर भारत सरकार ने इसकी अन्तिम किश्त 5,66,000 रूपये भी जारी कर दी। भारत सरकार ने राशी प्राप्त करने के लिये भेजे गये दस्तावेजों के मुताबिक खड़ा पत्थर का होटल गिरी गंगा प्रौजैक्ट 31-12-2001 को 39.30 लाख के कुल निवेश के साथ पूरा करके इस्तेमाल में भी ला दिया गया है। भारत सरकार के पैसे से बनी इस संपत्ति के प्रबन्धन का अनुबन्ध भी भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित कर दिया जाता है और किसी को भी इस पर कोई सन्देह नही होता है।

लेकिन जब 24-10-2005 का पर्यटन निगम के निदेशक मण्डल की वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक होती है तब इस होटल का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देशों के साथ इसे न लीज पर देने न बेचने का भी फैसला लिया जाता है। बैठक में इसे अप्रैल 2006 तक पूरा करके पर्यटकों के लिये उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये जाते है जिस होटल को भारत सरकार को 39.30 लाख में पूरा हुआ दिखवाया जाता है उसी को लेकर 20-02-2006 को प्रौजैक्ट अफसर द्वारा कमीशनर को लिखे पत्र में कहा जाता है कि इस पर अब तक 84.77 लाख खर्च हो चुका है और शेष बचे काम को पूरा करने के लिये 28,91,703 रूपये की और आवश्यकता होगी । प्रोजैक्ट अफसर के इस पत्र के बाद 31-5-2006 को इसके लिये तीस लाख रूपये और जारी कर दिये जाते हैं। इस तरह यह होटल 25-06-06 को 1,35,84,076 रूपये के निवेश से पूरा करके उद्घाटित कर दिया जाता है। यहां यह सवाल उठता है कि 31-12-2001 को कैसे कह दिया गया कि 39.30 लाख में होटल पूरा करके चालू कर दिया गया है। आगे चलकर यह खर्च कैसे बढ़ गये? इस निमार्ण को लेकर अरसे से सरकार के पास शिकायतें चल रही हैं। फारखा आज अतिरिक्त सचिव पर्यटन हैं और मुख्यमन्त्री के अपने पास विभाग है आज मुख्यमन्त्री के विश्वास के कारण फारखा मुख्य सचिव बन सकते है लेकिन क्या इससे पहले मुख्यमंत्री और फारखा को प्रदेश की जनता के सामने गोयल द्वारा उठाये गये सवालों पर जबाव नही देना चाहिये? या फिर यह जबाव अदालत के माध्यम से ही सामने आयेंगे?

iii) Hotel at Kharapathar

The Board of Directors after considering the various options decided not to sell/lease out the Hotel at Kharapathar at this stage. It was decided to expedite the completion of the Hotel so that it can be started before the coming tourist season in April, 2006. The Restaurant and Bar in the premises be started by February, 2006.

Om Parkash Goel,
M.Com, LLB and DPM & IR,
Advocate,
Mobile Phone: 94184 58533.
No.

Saint Albans Cottage,
Near Govt. Sr. Sec, School (Boys),
Shimla – 171 001.

Dated 20th May, 2016.

To

Shri Pranab Mukherjee,
His Excellancy President of India,
New Delhi.

Shri Narendra Modi,
Hon'ble Prime Minister of India,
New Delhi.

Dr. Dev Vrat Acharya,
His Excellency Governor,
Himachal Pradesh,
Shimla 2.

Shri Virbhadra Singh,
Hon'ble Chief Minister,
Himachal Pradesh, Shimla -2.

Shri Shanta Kumar,
Hon'ble M. P. Palampur. (H. P.).

Shri Sanjay Singh, Spokesperson, AAP. New Delhi.

Shri Rajan Shushant, Ex- MP, Conveneer, AAP (HP)

Subject: Request for the selection of the Chief Secretary of the Himachal Pradesh who is senior in the line but honest, competent, having good integrity and capable of maintaining the dignity of post of the Chief Secretary.

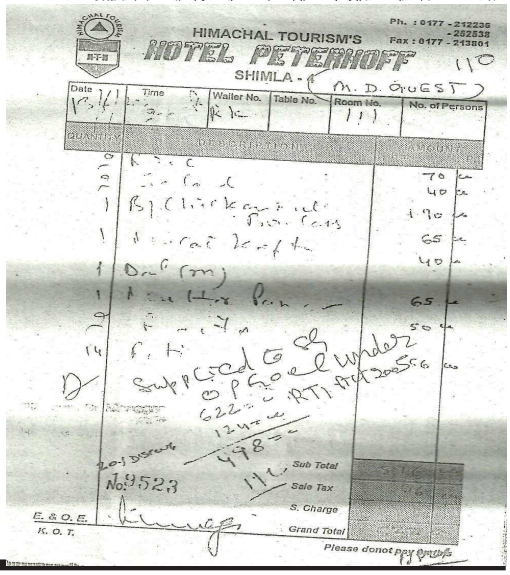

Sirs,

I may very humbly submit before your honour that Shri P. Mitra, Chief Secretary to the

राज्यपाल ने अनुपम खेर के अभिनय की जमकर की सराहना

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि संस्कारित समाज की संरचना के लिए हमें अपनी पुरातन संस्कृति को अंत:स्थल में बिठाना है ताकि यह देश पुन: विश्व गुरु का स्थान हासिल कर सके।

वह शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित तृतीय मनोहर सिंह स्मृति नाट्य समारोह के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि युवा पीढ़ी का अपनी संस्कृति से लगाव बनाए रखने के लिए उन्हें नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना जरूरी है। भारत की हमेशा से उच्च परम्पराएं एवं संस्कृति रही है। हमने समूचे विश्व को अपना परिवार माना और सभी के सुख की कामना की है। यह उच्च सोच और चिंता केवल हमारी संस्कृति में ही देखी जा सकती है।

आचार्य देवव्रत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जिस पुत्र के लिए माता-पिता अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, वही बुढ़ापे में बेसहारा हो जाते हैं। आज वे वृद्धाश्रमों में रहने के लिए मजबूर हैं, जो हमारी संस्कृति नहीं है। इसके लिए, हमें बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना आवश्यक है।

राज्यपाल ने इस मौके पर राकेश बेदी द्वारा निर्देशित नाटक 'मेरा वो मतलब नहीं था' की भरपूर प्रशंसा की और नाट्क के मुख्य कलाकार अनुपम खेर, नीना गुप्ता और राकेश बेदी के अभिनय की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके अभिनय ने नाट्क के माध्यम से दिए गए सदेश को दर्शकों के दिलों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अभिनय के माध्यम से इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण आसान नहीं है। समाज की विकृतियों को रंगमंच के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए कठिन परिश्रम व मेहनत की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ये कलाकार लोगों के दिलों में स्थान बनाने में सफल हुए हैं।

राज्यपाल ने अनुपम खेर, नीना गुप्ता और राकेश बेदी को हिमाचली शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। इससे पूर्व, सचिव, भाषा एवं संस्कृति विभाग अनुराधा ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया। विभाग निदेशक शशि ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने किया टूटीकंडी बाल आश्रम में शिशु गृह का उद्घाटन

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मूक बधिर, दृष्टि बाधित और विशेष योग्यता वाले बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत पुर्नवासित करने पर बल दिया, जिससे उन्हें आत्म-निर्भर बनाया जा सके और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। वह बाल आश्रम, टूटीकंडी में हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् द्वारा संचालित शिशु गृह के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल की धर्मपत्नी दर्शना देवी भी उनके साथ थी।

राज्यपाल ने इस बात पर संतोष जताया कि प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत 25 बाल व बालिका गृह चलाये जा रहे हैं, जिनमें लगभग 1100 बाल व बालिकाओं को नि:शुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग बाल आश्रम टूटीकंडी में रह रहे बच्चों के रहने, खान-पान और शिक्षा की जिम्मेवारी उठा रहा है और उनके विकास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने परिषद् को किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों का सख्ती से अनुसरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आश्रम में रह रहे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके चरित्र निर्माण पर भी बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे राष्ट्र की पूंजी हैं और मानवता के नाते आश्रमों में रह रहे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार मिलना चाहिए। मानव और पशु में केवल अंतर भी इसी बात का है कि मनुष्य अपने के साथ-साथ दूसरों के दुख-सुख को जानने की योग्यता रखता है।

उन्होंने कहा कि आश्रम के बच्चों से आहवान किया कि वे समाज के प्रहरी बनें और आशा जताई कि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर वे प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे।इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के और बेहतर खान-पान की व्यवस्था के लिए 11000 रुपये देने की घोषणा भी की।

प्रदेश सरकार सेवारत व पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रयासरत

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा इनके कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने सैनिक कल्याण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

डा. शांडिल ने कहा कि सैनिक विश्राम गृहों के जीर्णोधार व रख-रखाव के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है ताकि पूर्व सैनिक तथा सेवारत सैनिकों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में ट्राजिट फेसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध करवाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 1.95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और गत वर्ष शहीदों को 1. 14 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे पूर्व सैनिकों, जिन्हें कोई भी पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, को वृद्धावस्था पेंशन के तहत 6 करोड़ 40 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। डा0 शांडिल ने कहा कि वार जागिर के तहत भी 54 लाख रुपये सम्मान राशि के रूप में प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने परमवीर चक्र के तहत दी जाने वाली सम्मान राशि को एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये, अशोक चक्र के तहत दी जाने वाली सम्मान राशि को एक लाख से तीन लाख रुपये व महावीर चक्र प्राप्त करने वाले सैनिक को दी जाने वाली सम्मान राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख 25 हजार रुपये किया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों तथा सेवारत सैनिकों के कल्याण के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएं। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के सचिव मोहन चौहान, बिग्रेडियर राजेश कुन्दरा, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक बिग्रेडियर एस.के. वर्मा भी उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITIGN TENDER

Sealed item rate tenders are hereby the Executive Engineer , Hamirpur Division HPPWD Hamirpur in form No 6&8 on behalf of Governor of H.P. for the following woks from the contractors of appropriate class enlisted with HP,PWD The tender shall be opened in the presence of contractors/firms or their representative who wish to be present.

Time Schedule of Tender :

1. Date and time of receipt of application for tender from: 04-06-2016 to 4:00 P.M.
2. Date and time of issue of tender form : 06-06-2016 upto 4:00 P.M.
3. Date and time of receipt of tenders: 08-06-2016 upto10:30 A.M.
4. Date and of opening of tenders: 08-06-2016 at 11:00 A.M.

The request for issue of tenders should be on the PRESCRIBED APPLICATION FORM which can be obtained from the office of undersigned and tenders will be issued to only those contractors who quality the criteria after the scrutiny of application forms by the Committee constituted for this purpose.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost Rs	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender
1.	C/o link road to village Behal from Hamipu sujanpur road km 0/0 tp 4/0 (SH:- Providing mettalling /tarring in km 8/510 to 1/585)	721938.00/-	14450.00/-	Two Months	350/-
2.	Improvement of black spot on Darkoti Mohin road km 3/0 to 8/300 (SH:- C/o retaining wall at Rd 6/830 to 6/838)	174827.00/-	3500.00/-	Two Months	350/-
3.	Renovation of HPSEB Building at Hamirpur (SH:- c/os Toilet for mem-bers	148162.00/-	3000.00/-	Three Months	350/-
4.	S/R to 16 No. Qutrs at Hill Top Colony in Sainik School Sujanpur Tihra (SH:- P/L Tiles in Bath room toilets)	370465/-	7400/-	Two Months	350/-

1. The earnest money in the Shape of National Saving Certificate . Time deposit office in HP FDR of any Bank duly pledged in favour of Executive Engineer , Hamirpur Division HP PWD Hamirpur must be accompanied with the application for receipt of tender form along with cost form. Tender application received without earnest money will summarily be rejected.
2. The contractors /firms should possess the following documents (Photo copy to be attached with application for obtaining the tenders documents)
(i) Latest enlistment /renewal orders with application
(ii) For obtaining the tenders documents.
(iii) PAN (Permanent Account Number) issued by the Income Tax Department.
3. The Executive Engineer Hamirpur Division HPPWD. Hamirpur reserves the right to reject any tender without assigning any reasons(s)
4. The Cess Charges @ 1% will be deducted from the gross amount of work done by the Contractor.
5. A contractor enlisted in a particular class shall be eligible to tender for his own class and one step below.
6. Only one No. tender form will be issued to the eligible contractor.
7. If 8-6-2016 happens to be holiday the tender shall be opened on next working day at 11:00

Adv. No.-0597/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITIGN TENDER

Sealed item rate tenders on the form 6&8 are invited by the Executive Engineer fatehpur Division HPPWD , Fatehpur on behalf of the contactors enlisted in HPPWD.

Time Schedule of Tender :

1. Date and time of receipt of application for tender from: 13-06-2016 upto 4:00 P.M.
2. Date and time of issue of tender form : 14-06-2016 upto 5:00 P.M.
3. Date and time of receipt of tenders: 15-06-2016 upto10:30 A.M.
4. Date and of opening of tenders: 15-06-2016 at 11:00 A.M.

The tenders form will be issued against cash payment (non-Refundable) The earnest money in the shape of NSC/FDR Deposit at call of any of Post Office /Bank in H.P duly pledged in the Executive Engineer Fatehpur Division HPPWD Fatehpur must accompany with each tender.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost Rs	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender	Eligible Class of Contractor
1.	Construction of Badhwara Banker Kuther Nangal road km 0/0 to 6/0 (SH:- providing and laying soling Grade -I & wearing Grade -II in km 4/570 to 5/070 &s Metalling tarring in km 3/500 to 400 & 4/570 to 5/070) 9	85205/-	19750/-	One Month	350/-	Class D&C
2.	Construction of Malhari Kothi Bardial Smlet sroad km 0/0 to 3/0 (SH:- providing and laying 20mm thick premix capet surfacing including (IRCs types-B) seal coat in km 1/0 to 2/0)	678931/-	13600/-	One Month	350/-	Do-
3.	Construction of Sunhara Khadlow Nangal road km 0/0 to 8/860 (Under SCSP) (SH:- providing an laying soling Grade -in km 1/415 to 1/915, Wearing Grade -II in km 1315/to 1/815, to & Metalling tarring in km 1/315 to 1/ 815)and construction of 900mm dia Hume pipe culvert at RD . 1/415 & 1/570)	917460/-	18400/-	One Month	350/-	Do-
4.	Construction of Veterinary Dispenary Building at Badiali in Tehsil Fatehpur District Kangra H.P. (SH:- construction of Building portion including providing W.S. & S.I Construction of septic tank for 10 users, construtuion of boundary wall and Development at site)	897847/-	18000/-	Six Month	350/-	Do-
5.	A/R & M/o to Maira Palli Road km 0/ 0 to 8/870 (SH:- M/T of extended portion both sides at R.D. 4/045 to 5/045 (Under Black Spots)	438900/-	8800/-	One Month	350/-	Do-
6.	Special Repair to Fisheries Complex at Dhameta in Tehsil Fatehpur Distt. Kangra (HP) (SH:- special repair to 1 No type -III quarter)(Deposit work)	198966/-	4000/-	Three Month	350/-	Do-
7.	Special repair of PHC Building at Dhameta (SH:- Repair of wood wok, painting polishing and distempering work in ground floor & 1st floor)	83286/-	1700/-	One Month	350/-	Do-

1. The contractors /firms should posse the following documents (Photocopy to be attached)
(i) Latest renewal of enlistments.
(ii) PAN (Perment Account No.)
(iii) Registration under HP Gerenal Sale Tax Act, 1968 (TIN No.)
2. Ambiguous /telegraphic/ conditional tenders or tender by Fax E/mail shallnot be entertained /considered in any case .
3. The Executive Engineer reserves the right to reject /cancel any or all the tenders without assigning any reason(s)
4. Only two tenders shll be issued to each contractor

Adv. No.-0646/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

'पहल' शिमला जिला प्रशासन का एक अनूठा कार्यक्रम:वीरभद्र

शिमला/शैल। लोगों के जीवन को परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर कार्य करने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने एक अनूठी कार्यक्रम 'पहल' की शुरूआत की है। पहल एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा (प्रेरणा), लोगों को वनों के अधिकार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, नशा निवारण अभियान, आजीविका और महिला सशक्तिकरण के बारे जागरूक

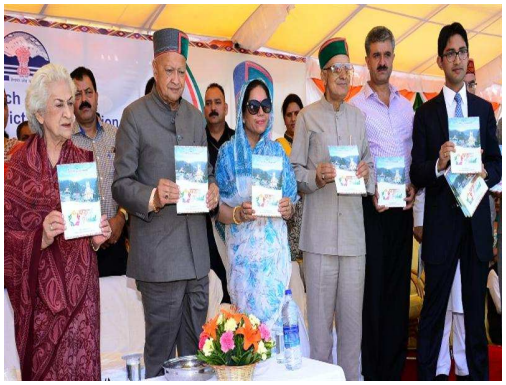

करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रेरणा' पहल का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो परिणाम में सुधार करने, संसाधन विकसित करने तथा प्राथमिक पाठशालाओं में अध्ययन स्तर में सुधार तथा आंकलन में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि प्रारम्भिक शिक्षा उच्च स्तर के अध्ययन का आधार हैं तथा कार्यक्रम की कमियों का पता लगाने तथा शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए शिक्षकों को इस ओर ध्यान देने के प्रति उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए समूचे शिमला जिले में 100 प्राथमिक पाठशालाओं में प्रेरणा की शुरूआत के लिए चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि इन कमियों का पता लगाकर विद्यार्थी के प्रदर्शन स्तर का स्वतंत्रतापूर्वक आंकलन किया जा सकता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र का संबंध है, हमें सुनिश्चित बनाना है कि हमारे आस-पास का वातावरण गंदगी मुक्त हो तथा स्वस्थ रहने के लिए हमें लोगों को सफाई एवं स्वच्छता की आदतों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामुदायिक भागीदारी से सम्पूर्ण स्वच्छता तथा जिले में 'पहल' के अन्तर्गत जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पहल' अभियान दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर केन्द्रीत है और जहां तक लोगों को वन अधिकारों में शिक्षित करने की बात है, उन्होंने जिला प्रशासन को जिले में पारम्परिक वन तैयार करने वालों के सामुदायिक अधिकारों से जुड़े सभी मामलों का निपटारा करने को कहा।

उपायुक्त शिमला रोहन ठाकुर ने कहा कि 'पहल' जिले के समग्र विकास के लिए विभिन्न हितधारकों को संघटित करने का एक प्रयास है, जिसमें संबंधित विभागों, पंचायतों, महिला तथा युवक मण्डलों को शामिल किया गया है ताकि इसे एक जन आन्दोलन बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि जहां तक स्वच्छता का संबंध है, जिले के तीन विकास खण्डों रामपुर, ननखड़ी तथा नारकण्डा में शत-प्रतिशत निजी घरों में शौचालय सुविधा है। उन्होंने कहा कि जिले में निजी घरों में शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए 6000 और शौचालयों की आवश्यकता है।

रोहन ठाकुर ने कहा कि लोगों को वन अधिकारों के बारे शिक्षित करना तथा उन्हें इन अधिकारों का लाभ पहुचाना भी 'पहल' के कार्य क्षेत्र में शामिल है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईइसी) अभियान चलाया गया है। इसके अतिरिक्त, आजीविका मिशन के अन्तर्गत लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान कर सशक्त बनाना भी 'पहल' के अन्तर्गत आरम्भ किया जाएगा, जिसमें मिस्त्री का कार्य, बिजली का कार्य, घरेलू उपकरणों व पलम्बर इत्यादि के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 'पहल' का उद्देश्य अर्ध-कुशल एवं कुशल महिलाओं, जिन्हें मुख्य सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है, के लिए संसाधन आधार का निर्माण करना भी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन 'पहल' में सम्मिलित किए गए नशा निवारण अभियान के अन्तर्गत युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए खेलों तथा मनोरंजक गतिविधियों के लिए अधोसंरचना में वृद्धि करने के भी प्रयास कर रहा है।

जनजातीय क्षेत्र में वरदान बनी टेली मेडिसन की पहल

शिमला/शैल। भौगोलिक परिस्थितियां तथा सीमित स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं जनजातीय जिला लाहौल एवं स्पिति में बहुमूल्य जिन्दगी को बचाने में बाधा नहीं बन सकी जब 31 वर्षीय मरीज को गम्भीर अवस्था में केलंग अस्पताल लाया गया। टेली स्वास्थ्य सेवाएं, केलंग के माध्यम से चेन्नई अपोलो अस्पताल के एक विशेषज्ञ की सायं समय पर जिला अस्पताल केलंग के चिकित्सक को सलाह मरीज को बचाने में सार्थक साबित हुई और उसकी हालत स्थिर हो गई।

स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि टेली मेडिसन की शुरूआत राज्य, विशेषकर दूरवर्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद रोगियों को आपातकाल के दौरान वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का चिकित्सा विज्ञान के साथ समावेश दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की चुनौतियों से निपटने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से गत एक वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्र में 2500 मरीजों को लाभान्वित किया गया है।

ठाकुर ने कहा कि टेली मेडिसन परियोजना का उद्देश्य साधारण दूरभाष के माध्यम से तथा दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों को सस्ती कीमत पर ब्रॉडबैंड दूरसंचार मीडिया का उपयोग कर विशेषज्ञ अस्पतालों के साथ इंटरैक्टिव चिकित्सा वीडियो सम्मेलन के माध्यम से चिकित्सा सलाह एवं परामर्श प्रदान करना है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह परियोजना आईजीएमसी शिमला में दूरवर्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों को आईजीएमसी के साथ जोड़ना सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में आरम्भ की गई थी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी अस्पताल की रोगी कल्याण समिति द्वारा विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए यह परियोजना वीडियो टेली कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में सीधा प्रसारण तथा दूसरी राय प्राप्त करने के लिए आईजीएमसी को प्रत्येक बुधवार को पीजीआई चण्डीगढ़ तथा प्रत्येक शनिवार को एसजी पीजीआई लखनऊ के साथ जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला को एम्स नई दिल्ली, रोहतक तथा लखनऊ से भी जोड़ा गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) विनीत चौधरी ने कहा कि टेली स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में मरीजों को आपातकाल में तुरन्त विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा एवं उपचार प्रदान करने में लाभकारी सिद्ध होगी। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को अपडेट रहने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य के लोगों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार भी आएगा।

काजा में सौर व पवन ऊर्जा परियोजना के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल।

प्रदेश ने सौर व पवन ऊर्जा क्षेत्र में नई शुरूआत करते हुएं हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने एक नये संयुक्त उपक्रम में सौर ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयन के लिए 'हिमाचल प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड' के गठन के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि. के प्रबन्ध निदेशक पी.सी. नेगी तथा भारत सरकार की ओर से भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबन्ध निदेशक अश्वनी कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन के तहत लाहौल स्पीति जिला के काजा के रंगरीक में 2.5 मेगावाट क्षमता का एक हाईब्रिड (सौर एवं पवन) विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य सितम्बर-अक्तूबर, 2017 रखा गया है। यह परियोजना भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसके तहत उच्च ऊर्जा भण्डारण की सहायता से सौर, पवन तथा जल विद्युत परियोजना का ग्रिड सप्लाई के साथ समायोजन किया जाएगा।

परियोजना के पूरा होने से रंगरीक, काजा, ताबो, लोसर, पिन घाटी तथा साथ लगते क्षेत्रों की 12000 से अधिक बस्तियां लाभान्वित होंगी। यद्यपि, मुख्यमंत्री ने जून 2014 में सौर परियोजना की आधारशिला रखी थी।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 30 करोड़ 72 लाख रूपये है, जिसमें से पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि 50 प्रतिशत राशि का वहन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

परियोजना में सालाना लगभग 4.41 मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन की आशा है जिसमें 3.32 मिलियन यूनिट पीवी मॉड्यूल तथा 1.09 मिलियन यूनिट पवन टरबाईन द्वारा तैयार होगी और उसे ग्रिड आपूर्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में बैक-अप बैटरी द्वारा सरक्षित भी किया जा सकेगा।

इस परियोजना के अतिरिक्त, सौर पार्क, सौर ऊर्जा परियोजनाएं व अन्य नवीकरण क्षेत्र परियोजनाएं जो व्यवहारिक होगी हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लि. तथा भारतीय सौर ऊर्जा निगम को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस परियोजना से राज्य में विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक ऊर्जा भी तैयार होगी और साथ ही प्रदेश में सौर व पवन ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक अवसर खुलेंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वी.सी. फारका तथा तरूण श्रीधर व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा भारतीय सौर ऊर्जा निगम के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विकासात्मक पत्रकारिता को पर्याप्त स्थान दें:मल्होत्रा

शिमला/शैल। पत्रकार समुदाय द्वारा पाठयेतर गतिविधियों में भाग लेने से उनके दैनिक व्यस्त जीवन में थकान से जहां सकून मिलता है, वहीं समुदाय के बीच निजी एवं

व्यावसायिक सम्बन्ध भी प्रगाढ़ होते हैं। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक दिनेश मल्होत्रा शिमला पत्रकार खेल एवं कल्याण संघ द्वारा आयोजित दो सप्ताह तक चली क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता व प्रतिभागी टीमों के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

मल्होत्रा ने पत्रकारों को इस बड़े एवं शानदार आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान में जहां व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति के पास समय का अभाव है, ऐसे में इस तरह के आयोजनों से सुकून की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की और अधिक गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए ताकि महिला पत्रकार भी इनमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के साथ सद्भावपूर्ण रिश्ते सुनिश्चित बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पत्रकार योजना आरम्भ करने की घोषणा की है, ताकि पत्रकारों को विषम परिस्थितियों, दुर्घटना व बीमारी इत्यादि के समय में तत्काल राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रेस क्लबों के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

मल्होत्रा ने पत्रकारों से विकासात्मक रिपोर्टिंग के लिए स्थान व समय प्रदान करने का आग्रह किया। इससे प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करने में सहायता मिलेगी तथा लोग इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे।

दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख प्रकाश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्रैस क्लब शिमला के प्रधान धनंजय शर्मा, शिमला पत्रकार खेल एवं कल्याण संघ के महासचिव राकेश सकलानी, प्रेस क्लब शिमला के अन्य पदाधिकारी तथा प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नही है। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

कांग्रेस की हार का अर्थ

चार राज्यों में हुए विधान सभा चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। केवल केन्द्र शासित पांड़िचेरी में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। इन राज्यों में पहले केरल और असम में कांग्रेस की सरकारें थी। इन राज्यों में कांग्रेस न केवल हारी है बल्कि शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इन राज्यों में हुए चुनावों से पूर्व बिहार विधान सभा के चुनाव हुए थे और वहां पर कांग्रेस आर जे डी और जे डी यू मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर रखने में सफल हो गये थे। बिहार में भाजपा को मिली हार के बाद यह राजनीतिक चर्चा चल पड़ी थी कि अब गैर भाजपा दल मिलकर भाजपा का आगे आने वाले चुनावों में सत्ता से बाहर रखने में सफल होते जायेंगे। बिहार की जीत के बाद नीतिश कुमार ने भी राष्ट्रीय राजनीति में आने के संकेत दे दिये। नीतिश के संकेतों के साथ ही कांग्रेस ने उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवाएं लेकर उनको यू पी की जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन इन चार राज्यों के चुनावों में भाजपा ने असम में शानदार जीत के साथ सरकार बनाने के साथ ही अन्य राज्यां में अपना वोट बैंक प्रतिशत बढाया है। इस चुनाव में भाजपा की असम जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कांग्रेस की हार।

कांग्रेस आज भी भाजपा से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। देश के हर गांव में उसका नाम जानने और लेने वाला मिल जायेगा। क्योंकि देश की अग्रेंजी शासन से स्वतन्त्रता का सारा श्रेय आज भी उसी की विरासत माना जाता है। देश की स्वतन्त्रता के समय यहां की सामाजिक स्थितियां क्या थी और उनसे बाहर निकाल कर आज के मुकाम तक पहुंचाने में कांग्रेस के गांधी – नेहरू पीढ़ी के नेताओं का जो योगदान रहा है उसे आसानी से भुलाया नही जा सकता। भले ही आज नेहरू का नाम स्कूली पाठ्यक्रमों से बाहर रखने का एक सुनियोजित ऐजैन्डा और उस पर अमल शुरू हो गया है लेकिन आज केवल गांधी – नेहरू विरासत के सहारे ही चुनाव नही जीते जा सकते है। देश को आजादी मिले एक अरसा हो गया है। आज सवाल यह है कि इस अरसे में देश पहुंचा कहां है? आज देश की मूल समस्याएं क्या हैं। आज भी सस्ते राशन के वायदे पर चुनाव लडा और जीता जा रहा है। दो रूपये गेहूं और तीन रूपये चावल के चुनावी वायदे अपने में बहुत खतरनाक हैं। इनके परिणाम आने वाले समय के लिये बहुत घातक होंगे। क्योंकि इस सस्ते राशन के लिये धन कहां से आयेगा? फिर क्या किसान इस कीमत पर अनाज बेच सकता है। लेकिन आज इन सवालों पर कोई सोचने तक को तैयार नही है। आज चुनाव खर्च इतना बढ़ा दिया गया है कि आम आदमी चुनाव लड़ने का साहस ही नही कर सकता हैं बल्कि चुनाव की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को राजनीतिक दलों के पास बंधक बनने के लिये विवश होने जैसी स्थिति बन गयी है। आज जिस तरह के चुनावी वायदे राजनीतिक दल करते आ रहे हैं और उनको पूरा करने की कीमत आम आदमी को कैसे चुकानी पड़ रही है उस पर अभी किसी का ध्यान नही है। लेकिन जब यह सवाल आम बहस का विषय बनेगें तब इसका परिणाम क्या होगा इसकी कल्पना से भी डर लगा है।

इस परिदृष्य में आज कांग्रेस जैसे बड़े दल का यह दायित्व है कि वह इन चुनाव परिणामों की समीक्षा अपनी विरासत की पृष्ठ भूमि को सामने रखकर करे। आज भ्रष्टाचार बेरोजगारी और मंहगाई ही देश की सबसे बड़ी समस्यायें और इनका मूल चुनावी व्यवस्था है। कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक जो कुछ खो चुकी है उसके पास शायद अब और ज्यादा खोने को कुछ नही रह गया है पंजाब और यू पी के चुनावों में भी कांग्रेस के लिये बहुत कुछ बदलने वाला नही है। ऐसे में यदि कांग्रेस अपने अन्दर बैठे भ्रष्ट नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देती है तो उसकी स्थिति में बदलाव आ सकता है अन्यथा नही।

हिमाचल देश का 'विद्युत राज्य' बनने की ओर अग्रसर

जहां तक जल विद्युत ऊर्जा का सम्बन्ध है, राज्य सरकार अकेले सार्वजनिक क्षेत्र में 265 मैगावाट बिजली का दोहन करने के प्रयास कर रही है। अब तक, राज्य में 10,264 मैगावाट जल विद्युत का दोहन हो पाया है, जिसमें से 830 मैगावाट बिजली का दोहन वर्ष 2015 – 16 के दौरान किया गया है

- **वर्ष 2015-16 में 830 मैगावाट जल विद्युत दोहन**
- **तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में 4200 ट्रांसफार्मर स्थापित**

हिमाचल प्रदेश के समस्त गांवों के विद्युतिकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उपरान्त अब राज्य सरकार जल विद्युत क्षमता के दोहन तथा उपभोक्ताओं को बिजली संचरण एवं वितरण पर विशेष ध्यान दे रही है।

सत्ता संभालते ही वर्तमान सरकार ने विद्युत क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र में आशातीत नतीजे सामने आए हैं।

समय पर स्वीकृतियों के अभाव में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी को रोकने के उद्देश्य से जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिये समयबद्ध स्वीकृतियां अथवा अनापत्ति प्रमाण प्रदान करने के लिये हि.प्र. लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत समय सीमा निर्धारित की गई है। राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत इस वित्त वर्ष के दौरान 65 मैगावाट की काशंग परियोजना, 100 मैगावाट की सैंज तथा 100 मैगावाट ऊहल जल विद्युत परियोजनाएं आरंभ हो जाएंगी। घानवी चरण – दो परियोजना के पूर्ण होने पर अतिरिक्त 10 मैगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा।

ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए राज्य में एलईडी प्रोत्साहन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को बाजार दरों से कम कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड ने ये एलईडी बल्ब भारत सरकार के उपक्रम 'ऊर्जा बचत सेवा सीमित' के माध्यम से प्राप्त किये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 22 लाख उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया गया है जिससे ऊर्जा संरक्षण में मदद मिली है और साथ ही उपभोक्ताओं को लम्बे समय तक चलने वाले बिजली के बल्ब भी उपलब्ध हुए हैं।

राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक संशोधित सौर ऊर्जा नीति तैयार की है। नीति के अन्तर्गत ग्रिड रुफ टॉप सौर परियोजना प्रस्तावित की गई हैं।

राजीव गान्धी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत चम्बा जिले के पांगी खण्ड को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में 33 के.वी. एच.टी. लाईन का कार्य पूरा कर लिया गया हैं। राज्य के 14 शहरों में कार्यान्वित किये जा रहे पुनरगठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डी, चम्बा, कुल्लू तथा ऊना शहरों में कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष शहरों में यह कार्य इस वर्ष दिसम्बर माह तक पूरा कर लिया जाएगा।

केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य में 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' भी आरम्भ की गई है। 159 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर, कुल्लू जिले के रायसन तथा मण्डी के थलौट में तीन नये विद्युत मण्डल तथा ऊना जिले के खाड, कांगड़ा जिले के मेक्लोड़गंज – टाण्डा में तीन विद्युत उपमण्डल खोले गए हैं।

प्रदेश सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का वित्तीय घाटा एक बड़ी चुनौती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय पुनरगठन तथा संसाधनों के समुचित उपयोग से इस घाटे से उभरने के प्रयास किये गए हैं। बोर्ड के वित्तीय पहलुओं में सुधार लाने की पहल करते हुए राज्य सरकार ने बोर्ड की 564 करोड़ रुपये की ऋण देनदारियों को अपनाया है और सरकार वर्ष 2016 – 17 के दौरान 56 करोड़ रुपये के ऋण भी चुकता करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड को नये खम्बे व ट्रांसफार्मर स्थापित करके ग्रामीण विद्युत लाईनों के सुधार के लिये 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हि. प्र. राज्य विद्युत बोर्ड ने विकसित वितरण प्रणाली पर 600 करोड़ रुपये का निवेश किया है तथा इस अवधि के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में 4200 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त, 33 किलोवाट के लगभग 23 विद्युत उप – केन्द्र, 132 किलोवाट के दो सब – स्टेशन, 220 किलोवाट का एक तथा 66 किलोवाट के तीन विद्युत उप केन्द्र क्रियाशील बनाए गए हैं।

हिमाचल ने शिक्षा में हासिल की उल्लेखनीय उपलब्धियां

शिमला। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों के दौरान साक्षरता स्तर, व्यापक एवं समान पहुंच में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य ने प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन दर लगभग 100 प्रतिशत हासिल कर ली है और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2017 तक हासिल करने की ओर अग्रसर है।

वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है। इसके लिये दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में नये प्राथमिक पाठशाला खोले जा रहे हैं और वर्तमान पाठशालाओं को स्तरोन्नत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार, मानदण्डों के अनुरुप राज्य के सभी प्रारंभिक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिये कटिबद्ध है जिसके लिये शिक्षा विभाग में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर हजारों नियुक्तियां की गई हैं।

राज्य सरकार राजकीय पाठशालाओं के विद्यार्थियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में स्कूल तक पहुंचने व वापिस घर तक निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य में यह योजना पहली अप्रैल, 2013 से कार्यान्वित की जा रही है।

प्रदेश सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1522 पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। अनुबंध पर कार्यरत 1497 टीजीटी अध्यापकों की सेवाएं पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर नियमित की हैं। वर्ष 2015-16 में 684 पैरा अध्यापकों (टीजीटी) की सेवाएं भी नियमित की गई हैं। पीटीए पर कार्यरत 919 टीजीटी अध्यापकों की सेवाओं को अनुबन्ध पर परिवर्तित किया है जबकि 356 जेबीटी और 59 सी एण्ड वी अध्यापकों को पदोन्नत किया गया है।

इसी अवधि के दौरान सी. एण्ड वी. अध्यापकों के 847 पदों को नई नियुक्तियों अथवा बैच आधार पर भरा गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान इस श्रेणी के 695 पैरा अध्यापकों की सेवाएं नियमित की गई हैं। पीटीए/ जीआईए पर कार्यरत सी. एण्ड वी. श्रेणी के 2307 अध्यापकों की सेवाएं अनुबंध पर की गई हैं। इसी श्रेणी के 97 अनुबन्ध अध्यापकों को नियमित करने के साथ-साथ सीधी भर्ती से जेबीटी के 1197 पद भरे गए हैं।

स्नातक अध्यापकों की पीटीए ग्रांट 6950 रुपये से बढ़ाकर 12510 रुपये तथा सी एण्ड वी अध्यापकों की ग्रांट 6750 रुपये से 12150 रुपये मासिक

की गई है। प्राथमिक सहायक अध्यापकों का मासिक मानदेय 7500 रुपये से बढ़ाकर 8900 रुपये करने के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा में जेबीटी से मुख्याध्यापक पदोन्नत होने पर एक वेतन वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है।

वर्तमान राज्य सरकार ने सेवा से बर्खास्त किये गए पीटीए अध्यापकों की सेवाओं को पीटीए नीति के अनुरुप बहाल करने का निर्णय लिया था जिसके अनुसार इन अध्यापकों के पदों को भरा हुआ माना गया।

राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान 210 प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने के अलावा 121 नये प्राथमिक पाठशाला खोले गए। नये स्तरोन्नत किये गए स्कूलों के लिये विभिन्न श्रेणियों के 830 पदों को सृजित किया गया।

प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के अध्ययन स्तर में सुधार एवं गुणात्मकता लाने के उद्देश्य से बाह्य रुप से पांचवी तथा आठवी कक्षाओं का आंकलन एवं मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया है। सभी अंशकालीन कर्मियों की सेवाएं 31 मार्च, 2014 को आठ वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत दैनिक भोगी कर्मियों में परिवर्तित की गई।

राज्य की विभिन्न पाठशालाओं में केन्द्रीय/राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत अंशकालीन जलवाहकों की नियुक्ति के लिये वांछित आय प्रमाण पत्र के लिये अधिकतम आय की सीमा को 12 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया गया है जिससे और अधिक लोग इन पदों के लिये पात्र होंगे।

अंशकालीन जलवाहकों का मासिक मानदेय पहली अप्रैल, 2014 में 1300 से बढ़ाकर 1500 रुपये तथा पहली अप्रैल, 2015 में इसे 1700 रुपये किया गया। राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में अंशकालीन जलवाहकों के 829 पदों को भरा गया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर क्लर्क-कम-डाटा एंट्री आप्रेटर के 164 नियुक्तियां की गई हैं। अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिये कार्यकाल को संशोधित कर छः वर्ष से पांच वर्ष किया गया।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों को सेवानिवृति के उपरांत सेवा विस्तार प्रदान किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना 14 सितम्बर, 2015 को गैर लाभदायी, स्वतंत्र एवं स्वायत संस्था के रूप में की गई जिसका कार्य क्षेत्र पूरा राज्य है।

कौशल विकास हेतु लक्ष्य समूहः

- ✔ हिमाचल प्रदेश की हिम कौशल नीति का उद्देश्य प्रदेश के 14 से 45 वर्ष के बीच की आयु के कम-से-कम कक्षा 5 उत्तीर्ण सभी युवा जिन्हें अपनी अर्जन क्षमता एवं जीवन स्तर बढ़ाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वे कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु प्राप्त होंगे।
- ✔ वे लोग जो पांचवीं या उससे ऊपर उत्तीर्ण हैं, योग्यता अनुसार आवश्यकता वाले पाठ्यक्रमों हेतु आवेदक हो सकते है।
- ✔ अकुशल/अर्धकुशल कामगार जो अपना कौशल स्तर बढ़ाना चाहते हों, कौशल विकास के लिए पात्र होंगे।
- ✔ समाज के वंचित वर्गों हेतू जैसे कि अल्पसंख्यकों, महिलाओं व दिव्यांगों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, साथ ही लक्षित समूह के अन्तर्गत समाज के सीमांत एवं दुर्बल वर्ग के वे लोग जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्तर पर लाभ लेने हेतु लघु अवधि के कौशल विकास पाठ्यक्रम चाहते हैं, पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का उपरोक्त लक्ष्य समूह से निवेदन है कि आप सभी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाएं। यह निगम एक माह के भीतर एक पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने जा रहा है जिसमें विभिन्न विषयों पर रोज़गार उन्मुखी तीन से छः माह तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा एवं तदोपरान्त पूरे राज्य में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण रूप से प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। यह पर ये बात आपके ध्यान लाना उचित होगा कि जो युवा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्राप्तांक प्रतिशत से उत्तीण करेगें उन में से 70% को रोज़गार प्रदान करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा पात्र युवाओं से आहवान किया जाता है कि वे विस्तृत जानकारी हेतू निम्नलिखित पते पर आवेदन कर सकते हैंः-

प्रबन्ध निदेशक,
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम,
310-बी., इलर्ज़ली भवन,
हिमाचल प्रदेष सचिवालय,
शिमला-171002
दूरभाष : 0177-2623481

प्रदेश सरकार राज्य के लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने में बुरी तरह विफल:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। नरेन्द्र मोदी सरकार के सुशासन के दो शानदार साल पूरा होने के कगार पर, अनुराग ठाकुर, सांसद हमीरपुर और अध्यक्ष BJYM ने हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सरकार के योगदान की सराहना की। मीडिया में जारी विज्ञप्ति के माध्यम से, अनुराग ठाकुर ने केन्द्र सरकार की उपलब्धियों और यहां के निवासियों की जिंदगी पर उनके प्रभाव का विशेष रूप से जिक्र किया। दूसरी ओर, उन्होंने आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की कमियां बताई।

केन्द्र सरकार की पहलों का ब्यौरा साझा करते हुए, अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के संरक्षण और अथाह नेतृत्व में, हमारा राष्ट्र एक विश्व राहनुमा बनने की दिशा में अग्रसर है। मोदी जी के सुधारात्मक उपायों और दूरदर्शी स्वप्न के साथ, पिछले दो साल में विश्व मानचित्र पर भारत का सकारात्मक रूप से विशेष उल्लेख किया गया है। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश को भी विकासात्मक परियोनजाओं और राज्य को आबंटित निधियों से अत्यंत लाभ हुआ है। अगर कुछ-एक पहलों का उल्लेख किया जाए तो संपर्क व्यवस्था में बढ़ाने के लिए 17 राष्ट्रीय राजमार्गों की हाल ही में स्वीकृति, पुलों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट, चिकित्सा कालेजों की स्थापना के लिए 600 करोड़ रुपये, रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। उससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी गई है जो संप्रग की सत्ताकाल में 32 प्रतिशत थी। 13वें वित्त आयोग में, हिमाचल को निधियों में 50% की बढ़ोतरी मिली थी जबकि 14वें वित्त आयोग में राज्य को 250: की बढ़ोतरी दी गई है। यह अगले पांच साल में राज्य के लिए 75,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान बनेगा जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा मिलेगा। यह पहलें रहे लोगों की सरकार की मंशाओं और उनके प्रगतिशील विधि को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।

उसी समय, कांग्रेस की राहनुमाई वाली हिमाचल सरकार राज्य के लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने में बुरी तरह विफल हुई है। ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं जहां वीरभद्र की सरकार ने कर्तव्य निर्वहन नहीं किया है जिसकी वजह से आम जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हाल ही की घटना है जिसमें हिमाचल में 16 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं के खराब प्रदर्शन ने अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता को जगजाहिर किया था। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी परेशान करने वाले हैं। शिक्षण के अपर्याप्त मानदंडों और शिक्षकों की कमी की वजह से यह असफलता हुई है। यह राज्य और उसकी उन्नति के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाता है। यह गंभीर चिंता की बात है क्योंकि युवा हमारा भविष्य हैं और इस पर पूरी निष्ठा एवं गंभीरता से कार्रवाई की जानी चाहिए। बच्चों की भविष्य की कीमत पर सरकार के इस लापरवाह ढर्रे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 26 मई 2016 को अपनी सत्ता के दो साल पूरा करेगी।

वृद्धजनों के कल्याण के लिए समेकित नीति का प्रभावी कार्यान्वयन

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में वृद्धजनों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हि.प्र. माता-पिता एवं आश्रित भरण-पोषण अधिनियम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अन्तर्गत बच्चों को उनके वृद्ध माता-पिता तथा अन्य आश्रितों की देखभाल अथवा उन्हें भरण-पोषण भत्ता देना अनिवार्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके कार्यान्वयन के लिए एसडीएम को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। इसके अन्तर्गत शिकायतों के निवारण के लिए शिकायतकर्ता सीधे एसडीएम को आवेदन कर सकता है और प्रतिमाह 5 हजार रुपये तक का गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तक 250 से अधिक लोगों ने इस अधिनियम का लाभ प्राप्त किया है।

उन्होंने कहा कि 'वृद्धजनों के लिए समेकित नीति' के अन्तर्गत सरकार ने मण्डी जिले के भंगरोटू, कुल्लू जिले के कालथ, कांगड़ा जिले के दाड़ी तथा शिमला जिले के बसन्तपुर में चार वृद्ध आश्रम खोले हैं। बसन्तपुर वृद्धाश्रम में 115 व्यक्तियों से अधिक की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे प्रदेश में केवल बसन्तपुर वृद्धाश्रम में क्षमता का 25 प्रतिशत विकलांग तथा अक्षम व्यक्तियों के लिए विकसित करने का निर्णय लिया है। मानसिक रूप से अक्षम व्यस्क विकलांग व्यक्तियों को कालथ में (60 महिलाओं), चुवाड़ी में (20 महिलाओं एवं 10 पुरूषों) और नाहन में (20 पुरूषों) के लिए तीन विशेष आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं। वर्तमान सभी गृहों से मानसिक रूप से विकलांग व्यस्क व्यक्तियों, नारी सदनों तथा अन्य आश्रमों से इन विशेष गृहों में धीरे-धीरे स्थानांतरित किया जाएगा।

डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार विभिन्न जिलों में 11 डे-केयर केन्द्रों तथा शिमला व कुल्लू में परामर्श केन्द्रों को सहायता प्रदान कर रही है। पिछले वर्ष के दौरान सरकार ने वृद्धाश्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए 47.89 लाख रुपये खर्च किए हैं। वर्तमान वर्ष के लिए 92 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, डे-केयर केन्द्रों तथा परामर्श केन्द्रों पर क्रमशः 20.54 लाख तथा 3.09 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1,97,876 व्यक्ति को वृद्ध पहचान पत्र जारी किए हैं, ताकि वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रदेश सरकार प्रति वर्ष प्रथम अक्तूबर को वृद्धजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय दिवस का आयोजन कर रही है।

डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में कुल 2,23,143 वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 80 वर्ष की आयु से कम के 1,56,082 व्यक्तियों को 650 रुपये प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 67,061 व्यक्ति को 1200 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने तथा वृद्ध लाभार्थियों को सुविधा सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार आरटीजीएस के माध्यम आधार आधारित पैंशन वितरण प्रणाली लागू करने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों के फलस्वरूप बिलासपुर तथा हमीरपुर में 80 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को पैंशन वितरण के लिए बैंकों से जोड़ा गया है तथा अन्य जिलों को भी सामाजिक सुरक्षा पैंशन लाभार्थियों से बैंक/पोस्टल बचत खातों का विवरण एकत्र करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो अति बुजुर्ग एवं अक्षम लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार पैंशन वितरण के लिए मनीआर्डर प्रणाली को जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री ने की स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में नर्सों के लिए अलग प्रकोष्ठ की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान कॉलेज एवं अस्पताल में अन्तरराष्ट्रीय नर्सिज दिवस के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में नर्सों के लिये एक अलग प्रकोष्ठ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य निदेशालय में एक अलग खण्ड का निर्माण किया जाएगा ताकि नर्सों का अपना कार्यालय हो।

उन्होंने नर्सों की मांग पर आहार भत्ता छः रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये करने की भी घोषणा की। उन्होंने

अनुबन्ध तथा रोगी कल्याण समिति के माध्यम से नियुक्त पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी नर्सों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने रोगी कल्याण समिति नर्सों को अनुबन्ध पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिये प्रतिबद्ध है, ताकि लोगों को उनके घर द्वार के समीप गुणात्मक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य के दूर-दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्वास्थ्य संस्थान खोले अथवा स्तरोन्नत किये जा रहे हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि आईजीएमसी की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी और पूर्व में इसे स्नोडन अस्पताल के नाम से जाना जाता था और आज आधुनिक उपकरणों एवं मशीनरी से सुसज्जित यह संस्थान अनुसंधान तथा गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का एक सुस्थापित केन्द्र बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि, संस्थान का काफी विस्तार किया जा चुका है, फिर भी सरकार लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शिमला शहर के उपनगर में अस्पताल का एक अलग परिसर स्थापित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी के अपने अलग परिसर के लिये प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑकलैण्ड सुरंग के समीप नया बहुमंजिला ओपीडी खण्ड का निर्माण, सुपर स्पैशियलिटी ब्लॉक तथा कमला नेहरु अस्पताल का नये ब्लॉक का निर्माण जैसी अस्पताल विस्तार की नई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि कोई संस्थान एक रात में नहीं बन जाता। यह एक जीवित शरीर की तरह होता है और एक पूर्ण संस्थान निर्माण के लिये समुचित योजना एवं लक्ष्यों का निर्धारण समाहित होता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार आने वाले समय में भी अस्पताल के लिये पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगी, ताकि मरीजों को उपचार के लिये राज्य के बाहर न जाना पड़े और गंभीर बीमारियों के उपचार पर अत्यधिक खर्च न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि कमला नेहरु अस्पताल के परिसर में एक अलग मातृ एवं शिशु राज्य अस्पताल बनाया जा रहा है जो आईजीएमसी का ही हिस्सा होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डी जिले के नेरचौक में ईएसआई अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज को भी सरकार अपनाएगी जिसके लिये बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक एवं पैरा मैडिकल स्टॉफ को समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए तथा अपनी कार्यशैली में मानवीय संवेदनाओं को शामिल करना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने नर्सों से बीमार एवं जरूरतमन्द लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाली फलोरेन्स नाईन्टिलगेल के आदर्शों का अनुसरण करने का आवाहन किया।

स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि नर्सों की चिकित्सकों से अधिक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वे रोगियों के उपचार के समय तथा बाद में एक उपकारी भूमिका का निर्वहन करती हैं। उन्होंने नर्सिंग एसोसियेशन की मांगों का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पैरा मेडिकल स्टॉफ के 4025 पद स्वीकृत करने के अलावा आईजीएमसी तथा मेडिकल कॉलेज नाहन में नर्सों की कमी को पूरा करने के लिये नर्सों के 377 पदों को भरने का मामला सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि नर्सों के अलग सेल के लिये धनराशि प्राप्त हो चुकी है तथा इसपर भी विचार किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने आर.के.एस. नर्सों को अनुबन्ध पर नियुक्त करने तथा पांच वर्ष सेवाओं के उपरान्त उन्हें नियमित करने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने लिंग अनुपात में सुधार के लिए नर्सों से बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य के लाहौल-स्पिति जिले का लिंग अनुपात देश भर में सर्वश्रेष्ठ है और यहां 1000 पुरूषों पर 1033 महिलाएं हैं।

बिजली कनेक्शन को उद्योग विभाग, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, फायर विभाग से एन.ओ.सी. जरूरी नहीं

शिमला/शैल। भारतीय उद्योग परिसंघ ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया और कनेक्शन दिए जाने के प्रोसस को सरल करने की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से प्रदेश में व्यापार करने के अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन संजय खुराना ने कहा कि हिमाचल सरकार लगातार राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल तैयार कर रही है और बिजली के कनेक्शन के अलावा हलफनामा प्रक्रिया को बदल कर स्वयं सत्यापन आदि कई ऐसी व्यवस्था हैं जो नए उद्योगों को स्थापित होने के लिए अनुकूल माहौल देते हैं।

खुराना ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिजली कनेक्शन के लिए उद्योग विभाग, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड व फायर विभाग से एन.ओ.सी. की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब यह केवल टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 के आधीन आने वाले प्लानिंग एरिया पर ही लागू होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि कानूनी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं लेकिन कम से कम बिजली के कनेक्शन के लिए इन्हें नहीं सौंपना होगा। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं को आसान बनाकर राज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल बढ़ा है जिससे राज्य में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही निवेशकों की इस राज्य में दिलचस्पी बढ़ी है और इससे यह पहाड़ी राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे राज्य भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश साबो ने कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा सुझावों को गंभीरता से लेने पर उनका आभार जताते हैं। नियमों को उद्योगों के अनुरूप बनाना राज्य की तरक्की की राह में मील का पत्थर साबित होगा और शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश उद्योगों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर सामने आएगा।

भरमौर में शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होगें 2 करोड़ 90 लाख रूपये:भरमौरी

शिमला/शैल। जनजातिय क्षेत्र भरमौर उपमण्डल के प्रघाला पंचायत में स्तरोन्नत राजकीय उच्चविद्यालय सठली का वन एवं

मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने विधिवत रूप से लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा घर द्वार पर शिक्षा मुहईया करवाना सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। जनजातिय क्षेत्र भरमौर में इस वितिय वर्ष जनजातिय उप योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र में 2 करोड़ 90 लाख रूपये की राशि शिक्षा व ढांचागत कार्यो पर व्यय किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के जनजातिय व गैरजनजातिय क्षेत्रों का एक समान रूप से विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

वन मंत्री ने पालदा, प्रघाला व खुंड सम्पर्क मार्गो को स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा कि जून माह में इन मार्गो का शिलान्यास किया जाएगा और लोक निर्माण विभाग को आदेश देते हुए कहा कि शीघ्र ही इन मार्गो का प्राकल्यन तैयार करें और कुगति सडक मार्ग के कार्य में तेज गति प्रदान करें ।उन्होंने कहा कि पट्टी में अस्पताल के लिए भूमि चयनित करने के उपरान्त भूमिहस्तारण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। शीघ्र ही भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। सठली विद्यालय के मुख्यध्यापक योगेन्द्र ठाकुर ने वनमंत्री को शॉल एवं टोपी पहना कर सम्मानित किया और प्रघाला पंचायत के प्रधान संजय ठाकुर तथा टीएसी मेम्बर भजन ठाकुर तथा प्रधानाचार्य भरमौर ने अपने विचार रखे। बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर ठाकुर सिंह भरमौरी ने अपनी एच्छिक निधि से 5000 रू0 देने की घोषणा की।

कौल सिंह के आदेशों की अनुपालना नहीं कर रहे राजस्व अधिकारी

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह द्वारा गत 16 अप्रैल को मशोबरा ब्लॉक की पंचायत पीरन के गांव टूहाई के प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों की मांग पर नायब तहसीलदार जुन्गा को निर्देश दिए थे कि पटवारी सप्ताह में चार दिन पीरन और दो दिन जनेडघाट में लोगों के कार्य के लिए उपस्थित रहेगें। परन्तु खेद का विषय है कि एक माह बीतने के उपरांत भी राजस्व मंत्री के आदेशो की अनुपालना नहीं हुई।

पूर्व प्रधान बालक राम निर्मोही, प्रीतम ठाकुर, देवेन्द्र कुमार, राजेश, सुरेश सहित अनेक लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा पटवारी की पोस्टिंग पीरन की गई है और इन्हें जनेडघाट पटवार सर्कल का अतिरिक्त कार्यभार देकर उन्हें जनेडघाट बिठा रखा है जिस कारण पीरन पंचायत के लोगों को लगभग 32 किमी बस में सफर करके राजस्व संबधी कागजात लेने के लिए जनेडघाट जाना पड़ता है और कई बार पटवारी न मिलने से निराश वापिस भी आना पड़ता है साथ ही पूरा दिन बर्बाद हो जाता है।

पंचायत के लोगों ने हैरानी जताते हुए कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए ठाकुर कौल सिंह के आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं, जबकि कौल सिंह ने जनसभा में नायब तहसीलदार जुन्गा को तुरंत पीरन भेजने के आदेश दिए थे परन्तु एक माह बीतने पर भी समस्या जस की तस बनी हुई है और लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं।

उन्होने भू-व्यवस्था विभाग पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पीरन गांव का बंदोबस्त होने के बावजूद गत एक साल से इस गांव का भूमि रिकार्ड राजस्व विभाग को नहीं सौंपा है, जिस कारण पीरन गांव के लोगों को छुटपुट कागजात के लिए कोटी जाना पड़ता है और विडंबना यह है कि बंदोबस्त पटवारी किस्मत से ही कोटी में मिलते हैं।

पीरन पंचायत के लोगों की राजस्व मंत्री और उपायुक्त शिमला से गुहार है कि पटवारी को पीरन में पुनः आदेश जारी किए जाऐं और पीरन गांव का भूमि रिकार्ड नायब तहसीलदार जुन्गा को सौंपने के लिए बंदोबस्त विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाऐ ताकि लोगों को जमाबंदी व अन्य प्रमाण के लिए जनेडघाट व कोटी न जाना पड़े।

समाज में बदलाव के लिये सोच में परिवर्तन आवश्यकता:कौल सिंह

शिमला/शैल। महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक उत्थान में अह्म योगदान है। इसके लिये महिलाओं का स्वंय सशक्त होना आवश्यक है। समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है तभी उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व तथा विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिमला स्थित महिला प्रभाग द्वारा 'बेटी बचाओ, सशक्त बनाओ' अभियान के शुभारम्भ पर कही। जन जागृति के इस अभियान का समापन आगामी 6 जून को समापन धर्मशाला में होगा।

कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान तथा उन्हें स्वाबलम्बी बनाने के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनमें 'बेटी है अनमोल योजना', 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना', मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना इत्यादि। इसके अतिरिक्त, लड़कियों को प्रथम कक्षा से स्नात्कोतर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सक्षम बनाने के लिये पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है जिसके चलते आज प्रदेश में लगभग 58 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित होकर राजनीति में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महिलाओं को उनके घर-द्वार के समीप अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखने के उद्देश्य से राज्य के दूर-दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान 30 महाविद्यालय खोले गए हैं तथा अनेकों पाठशालाओं को जमा दो में स्तरोन्नत किया गया है। परिणामस्वरूप इन शिक्षण संस्थानों में वर्तमान में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। उन्होने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रान्ति से यहां की महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है तथा पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के विकास में पूर्ण सहयोग कर रही हैं।

प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हई प्रगति पर चर्चा करते हुए ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मानकों में देशभर में अब्बल है। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26000 रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रही है। राज्य में 12391 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक मौजूद है तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या भी अनुपात दृष्टि से देशभर में श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रसव पूर्व लिंग जांच रोकथाम अधिनियम (पीएनडीटी) का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या महापाप ही नही, बल्कि कानूनन जघन्य अपराध है और अधिनियम में इसके लिये कड़ी सजा का प्रावधान है। हालांकि, इस दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य के कुछ भागों में लिंग अनुपात में कमी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कन्याओं के प्रति सोच को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पिति में लिंग दर 1000/1033 है जो देश व प्रदेश के लिये एक बेहतर उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि बेटा-बेटी में भेदभाव संकीर्ण मानसिकता है और इससे बचना चाहिए। बेटियां बिना किसी स्वार्थ के माता-पिता की जीवन पर्यन्त सेवा करती हैं और यहां तक कि सभी प्रकार के कर्मकाण्ड करवाने में भी पीछे नही हैं।

इसके पश्चात, स्वास्थ्य मंत्री ने 'बेटी बचाओ, सशक्त बनाओ' अभियान रैली को हरी झण्डी दिखाकर इसके प्रस्थान की रस्म को पूरा किया।

माउन्ट आबू से आई अभियान की मुख्य संचारिका ब्रह्माकुमारी डा. सरिता ने कहा कि हमारे देश में सदियों से नारी की पूजा की जाती रही है, लेकिन यह बिडम्बना ही है कि इसके बावजूद भी महिलाओं पर जुर्म की दास्तां में विशेष कमी नही आई है। उन्होंने कहा कि समाज में दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं एवं सामाजिक मान्यतांए बेटी को पनपने से रोकती हैं। बेटे से वंश चलता है, इस अवधारणा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। उन्होंने बेटी की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बेटी शिक्षित होने से समाज की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनती है।

ब्रह्माकुमारी सुषमा ने कहा कि नारी में आत्म सुरक्षा, आत्म सम्मान तथा आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इसके लिये लड़कियों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं राजनीतिक, समाजिक, सुरक्षा, कानून व व्यवस्था सभी क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

गीरीपार क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने की मांग की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिह से सिरमौर जिला के गीरीपार क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमण्डल रोजगार सृजन एवं रिसोर्स

मोबलाईजेशन बोर्ड के अध्यक्ष हर्ष वर्धन चौहान के नेतृत्व में मिला तथा गीरीपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग की। प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को शीघ्र सौंपी जाए।

हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि सिरमौर जिले के शिलाई व रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की राजगढ़ तहसील और पांवटा विधानसभा क्षेत्र के आंजभोज क्षेत्र की 8 पंचायतों के लोग इस क्षेत्र को लम्बे समय से जनजातीय दर्जा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह क्षेत्र जनजातीय घोषित होता है, तो अढ़ाई लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्षी जी. आर. मुसाफिर, केन्द्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर और सिरमौर युवा विकास मंच के सदस्यों के अतिरिक्त अनेक लोग प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि मामले को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाएगा।

5वें राज्य वित्तायोग की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने 5वें राज्य वित्तायोग की बैठक की अध्यक्षता की।

कुलदीप कुमार ने शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थानों की राजस्व क्षमता एवं व्यय आवश्यकताओं का समुचित आकलन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अध्यक्ष ने उपलब्ध विश्वसनीय संसाधनों से प्राथमिक डाटा को सेकेण्डरी डाटा के साथ मिलान करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने शहरी विकास और पंचायती राज विभागों को अपना मेमोरेंडम शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा।

पंचायती राज के सचिव एवं आयोग पदेन सदस्य अक्षय सूद तथा शहरी विकास विभाग के निदेशक जी.एम. पठानिया ने आश्वासन दिया कि वांछित सूचना यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

दिल्ली उच्च न्यायालय का वीरभद्र को दस्तावेज देने से इन्कार

और हिमाचल उच्च न्यायालय ने आनन्द चौहान से पूछा मेनटेनेबिलिटी का आधार

शिमला/शैल। सीबीआई और ईडी द्वारा वीरभद्र के आवास और अन्य स्थानों पर की गयी छापामारी के आधार बने तथा जांच के दौरान जुटाये गये दस्तावेज उन्हे सौंपने की गुहार दिल्ली उच्च न्यायालय से लगाई थी जिसे अन्ततः अदालत ने अस्वीकार कर दिया है।

लेकिन यह रिकार्ड अदालत के सामने अश्वय रखा जायेगा जिससे यह सन्तोष किया जा सके की जांच ऐजैन्सी ज्याती नही कर रही है। अदालत ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जांच के दौरान रिकार्ड देने का कोई प्रावधान नही है। इस अस्वीकार का असर ईडी द्वारा की गयी संपति अटैचमैन्ट के आदेश को निरस्त करने की गुहार पर भी पड़ सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अस्वीकार के बाद यह माना जा रहा है कि अब जल्द ही चालान अदालत तक पहुंच जायेगा। क्योंकि 173 सी आर पी सी के तहत जो रिपोर्ट अदालत में फाईल होने की जो अनिवार्यता ई डी के 2002 के मूल अधिनियम में थी वह जनवरी 2013 में अधिसूचित हुए संशोधन में समाप्त कर दी गयी है।

दूसरी ओर वीरभद्र के साथ सह अभियुक्त बने आनन्द चौहान और चुन्नी लाल ने भी मामलों में अब हिमाचल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने लिये उसी तर्ज पर राहत मांगी है। प्रदेश उच्च न्यायालय में इतनी देर बाद आयी इस याचिका पर रजिस्ट्री में कुछ एतराज लगाये गये थे जिन्हे दूर करने के बाद सुनवाई के लिये आयी इस याचिका पर अदालत ने इसकी मेनटेनेबिलिटी का आधार आनन्द चौहान से पूछा है। इस याचिका पर प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक हल्कों में अलग तरह की अटकलों का दौर चल पड़ा है।

क्योंकि यदि आनन्द चौहान और चुन्नी लाल ने यह याचिका उसी समय डाल दी होती जब वीरभद्र को राहत मिली थी तब इसको लेकर कोई और सवाल न उठते। लेकिन अब जब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो चुका है तब भी इस याचिका का हिमाचल उच्च न्यायालय में दायर किया जाना कई सवालों को जन्म देता है क्योंकि जब यह याचिका हिमाचल उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिये आयी उसी दिन दिल्ली उच्च न्यायालय मे ई डी ने वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, आनन्द चौहान, चुन्नी लाल और विक्रमादात्यि तथा अपराजिता सिंह को तलब कर रखा था। इस पूरे परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि इस प्रकरण में शीघ्र ही कुछ बड़ा घटने वाला है।

सचिवालय से मन्त्री नदारद क्यों

वीरभद्र के मन्त्री प्रदेश सचिवालय से अकसर नदारद देखे जा रहे हैं। मीडिया में यह नदारदगी सुर्खियां भी बटोर चुकी है। इस पर वीरभद्र कई बार मन्त्रियों को नसीहत और निर्देश भी जारी कर चुके हैं कि वह कम-से-कम सप्ताह में तीन दिन सचिवालय में रहकर लोगों की समस्याएं सुने और उन पर काम करें। सुधीर शर्मा पर तो मुख्यमन्त्री गैर हाजिरी को लेकर व्यगात्मक उलाहना भी कर चुके है। लेकिन मुख्यमन्त्री के निर्देशों का विद्या स्टोक्स और धनीराम शाडिल के अतिरिक्त और किसी पर कोई असर नही हुआ है और इनका यह है कि इनके पास और कहीं जाने की जगह ही शायद नहीं है। मन्त्रियों का असर बड़े बाबूओं पर भी बराबर देखने को मिल रहा है कुछ अधिकारी तो नियमित रूप से हर सप्ताह दो-तीन दिन तक सचिवालय में नदारद रहते हैं। मजे कि बात तो यह है कि यह मन्त्री लोग अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के बाहर भी नहीं देखे जा रहे है।

सचिवालय से मन्त्रियों का लगातार नदारद रहना जनता के लिए चिन्ता और चिन्तन का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि मुख्यमन्त्री भी यदि दिल्ली की यात्रा पर नहीं है तो वह भी प्रदेश के किसी-न-किसी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर ही रहते हैं। मुख्यमन्त्री के निर्देशों का उनके मन्त्रियों पर असर क्यों नही हो रहा है जब इस बारे थोड़ी जानकारी जुटायी गई तो यह सामने आया है कि वीरभद्र के मन्त्री ही मुख्यमन्त्री की हर गतिविधि पर पूरी बारीकी से नजर रख रहे हैं। दिल्ली में सीबीआई और ई.डी. के मामलों में कब क्या हो रहा है यह उनको वीरभद्र से ज्यादा जानकारी है। मुख्यमन्त्री कब हाई कमान के किस सूत्र से मिल रहे हैं और हाई कमान का नजरिया उनको लेकर क्या चल रहा है इसकी भी पूरी खबर ये लोग रख रहे हैं। कुछ लोग तो कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद के माध्यम से इनके केसों की भी पूरी जानकारी रख रहे हैं। ऐसे ही एक जानकार का दावा है कि इन वकीलों ने वीरभद्र के साथ-साथ हाई कमान को भी इन केसों के संभावित अन्तिम परिणामों से आगाह भी कर रखा है। चर्चा है कि इसी सबको सामने रख कर वीरभद्र सिंह ने हाई कमान को पंजाब से पहले ही प्रदेश विधानसभा के चुनाव करवा लिए जाने का सुझाव तक दे रखा है। छठी बार मुख्यमन्त्री बने वीरभद्र की राय को हाई कमान ने पूरी गम्भीरता से लिया है। लेकिन इनकी जानकारी जैसे ही बाकी मन्त्रियों तक अपने-अपने सूत्रों से पहुंची है तभी से उन्होंने भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का रूख कर लिया है।

बागियों को ठिकाने लगाने की तैयारी में भाजपाई व कांग्रेसी

शिमला/शैल। कांगड़ा के बाद सरकार बनाने में सबसे अधिक योगदान देने वाले मंडी जिला की करवट इस बार नेताओं के होश उड़ाने को तैयार है। बेशक विधानसभा चुनाव को एक साल से भी अधिक समय शेष है लेकिन भाजपा और कांग्रेस चुनावी मुद्दों की तलाश आज से ही करने को मजबूर हैं। मंडी में फिफ्टी-फिफ्टी से आगे बढ़ने के लिए दोनों प्रमुख दल बिसात बिछाने लगे हैं। इस होड़ में भाजपा ने पहल की है। भाजपा जहां फोर लेन, ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज नेरचौक, जोगेंद्रनगर मंडी ब्राडगेज रेल सर्वे, पठानकोट-जोगेंद्रनगर ब्राडगेज तथा नए एनएच की मंजूरी जैसे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंच चुकी है, वहीं कांग्रेस के मंडी से तीन मंत्री एवं दो सीपीएस भी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के सहारे जनता से तालमेल बैठाने के लिए डट चुके हैं।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का मई का प्रस्तावित मंडी दौरा जहां विकास की कई घोषणाओं, शिलान्यासों एवं उद्घाटनों से मंडी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा वहीं कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी के लिए उत्साहित करेगा। उधर पहली बार सांसद बने रामस्वरूप शर्मा अपने दो साल के कार्यकाल के दौरान केंद्र से मिली सौगातों का पिटारा लेकर जनता के बीच घूम रहे हैं जिससे भाजपा को निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 जून के अपने मंडी दौरे के दौरान कई सौगातें जिला को देकर भाजपा को मजबूती प्रदान करेंगे। बताते चलें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के लगातार मंडी दौरों के बाद कांग्रेस अलर्ट हो गई है। धूमल के नेतृत्व में भाजपा मंडी की पांच सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ ही अन्य पांच सीटें कांग्रेस से छीनने की फिराक में है। भाजपा गत चुनावों में बगावत की वजह से पांच सीटें मंडी जिला से गंवाने की गल्ती को इस बार नहीं दोहराना चाहेगी। इसके लिए भाजपा हारी हुई सीटों पर हार के कारणों का मंथन कर पहले से ही रणनीति बनाने में वयस्त है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता को लेकर भी दोनों दल अपने कुनबे को संभालने में लगे हुए हैं। आप की नजर भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्टों पर टिकी हुई है।

जिला से ज्यादातर चुनावों में हालांकि कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन छोटी काशी की करवट का अंदाजा लगाना मंडी के नेताओं के लिए भी मुश्किल हो गया है। 1993 के चुनावों पर नजर डालें तो उस समय एक तरफ कांग्रेस ने मंडी से नौ सीटें प्राप्त की थी। इसके बाद 1998 में भी भाजपा की दो सीटों के मुकाबले कांग्रेस को मंडी से चार सीटें मिली। 2003 में सत्ता में आने के समय मंडी से कांग्रेस को छह सीटें मिली थी जबकि भाजपा के खाते में दो ही सीटें आई थी। 2012 के विस चुनाव में द्रंग, धर्मपुर, सराज, सरकाघाट और जोगिंद्रनगर में कांटे की टक्कर रही जिसमें द्रंग को छोड़ अन्य सीटें भाजपा के खाते में रही। बल्ह, नाचन, मंडी सदर, करसोग और सुंदरनगर में पकी खिचड़ी से कांग्रेस व भाजपाई, दोनो दलों के पसीने छूट गए थे। बागियों और आजाद उम्मीदवारों ने पांच सीटों को दोनो पार्टियों के लिए डेंजर जोन बना दिया था। दोनो दल इस बार फिफ्टी-फिफ्टी की स्थिति से आगे निकलने के लिए जोर लगाएंगे।

मंडी जिला में वर्तमान में कांग्रेस के पास मंडी सदरए बल्ह, सुंदरनगर, करसोग, और द्रंग सीटें हैं जबकि भाजपा के पास सराज से जयराम ठाकुर, जोगिंद्रनगर से गुलाब सिंह ठाकुर धर्मपुर से महेंद्र सिंह ठाकुर सरकाघाट से कर्नल इंद्र सिंह और नाचन से विनोद कुमार पांच विधायक है। गत विस चुनावों के अलावा इस बार हुए पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में भी कांग्रेस में काली भेड़ों व भाजपा के कुछ बागियों ने चुनावी समीकरण बदलने में अहम भूमिका निभाई। भाजपा और कांग्रेस चुनावी मुद्दों के साथ ही काली भेड़ों और बागियों पर विशेष नजर रखने के लिए पहले से ही मजबूर है। कांग्रेस काली भेड़ों और भाजपा बागियों को ठिकाने लगाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में मंडी की राजनीति का पारा चढ़ने के साथ ही राजनीतिक महौल गर्माने की तैयारियां शुरू हो गई है।

प्रदेश उच्च न्यायालय में HPCA पर फैसला सुरक्षित

अनुराग ठाकुर बने BCCIअध्यक्ष

शिमला/शैल। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी रोकने की मुहिम कामयाब नही हो पाई। यही नही जस्टिस लोढ़ा कमेटी की चार्जशीटेड लोगों के बीसीसीआई के पदाधिकारी न बनाने की सिफारिश भी दिल्ली क्रिकेट अकादमी के पूर्व अध्यक्ष व वित मंत्री अरुण जेटली के चहेते अनुराग ठाकुरको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने से नही रोक पायी।

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये पद बीसीसीआई के अध्यक्ष मनोहर शंशाक के इस्तीफा देने से खाली हुआ था। अनुराग ठाकुर का बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए बड़ी बात है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की सता संभालते ही अनुराग ठाकुर की एचपीसीए के खिलाफ एक के बाद एक करके कई मामले दर्ज किए थे। अनुराग ठाकुर के खिलाफ कई मामले अदालतों में लंबित हैं। इन्ही मामलों को आधार बनाकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोका जाए। अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की पीठ में सुना जाना है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने दलील दी है कि जसिटस लोढ़ा कमेटी ने सिफारिश कर रखी है कि राजनेताओं व चार्जशीटेड लोगों को बीसीसीआई के किसी भी पद पर न तैनात किया जाए। बावजूद इसके अनुराग ठाकुर ने अध्यक्ष पद पर अपनी ताजपोशी करवा ली है। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को नही माना है।

उनके अध्यक्ष बनने पर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने खुशी जताई है।माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर की इस ताजपोशी का प्रदेश भाजपा के भीतरी समीकरणों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस ताजपोशी से प्रेम कुमार धूमल को और ज्यादा ताकत मिलेगी।प्रदेश सरकार अनुराग की HPCA के खिलॉफ अबतक जो स्टैन्ड लिये हुए है वह कितनाजारी रहेगा या उसमें कोई तबदीली आयेगी ये भी आने वाले दिनों मे देखने को मिलेगा। यह एक संयोग माना जा रहा हैं कि अनुराग की ताजपोशी के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय में HPCA को सोसायटी से कंपनी बनाये जाने का जो मामला काफी अरसे से लंबित चल रहा था उसमे अब फैसला सुरक्षित हो गया है। यह फैसला घोषित होने पर ही पता चलेगा कि HPCA का सोसायटी से कंपनी बनाया जाना सही था या गल्त । इस फैसले का भ्च्ब् के भविष्य पर विशेष असर पड़ेगा। यदि यह फैसला HPCA के पक्ष में आता है तो क्या वीरभद्र सरकार इसमें अपील मे जायेगी या नही इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। क्योकि पिछले दिनों जिस तरह से धूमल -वीरभद्र और विक्रमादित्य में विशेष मुलाकात हुई है उसका भी असर इन बदली परिस्थितियो में सबके लिए विशेष जिज्ञासा का विषय रहेगा।